>

Title: Need to monitor the process of procurement of agricultural produce in order to ensure full and timely procurement of such produce at Government rates from farmers.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य जिन्सों के समर्थन मूल्य तय करके क्रियान्वित करने के निर्देश राज्य सरकार को दिये जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के निदेशों की पालना समय पर नहीं की जाती है , जिससे किसानों को भरी नुकसान होता है। उदाहरणस्वरूप राजस्थान में मूंगफली की पैदावार किसानों की मेहनत के कारण दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जब फसल बाजार में आने लगती है तो सरकारी खरीद की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ नहीं होती है। 15-20 दिन या कभी - कभी एक महीना ऐसे ही निकाल दिया जाता है। जब सरकारी खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो समुचित भंडारण का बहाना लेकर मण्डी में आने वाली पूरी फसल को नहीं खरीदा जाता है एवं किसान परेशान होता रहता है। इस तरह की अव्यवस्था का दौर वर्तमान में मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर शहर की मण्डियों में तथा लूनकरणसर, नोखा एवं श्रीडूंगरगढ़ की मण्डियों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। मेरा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से मांग है कि जितनी भी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य मंत्रालय द्वारा तय किये जाते हैं उसकी खरीद समर्थन मूल्य के आधार पर हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी केन्द्र सरकार के मंत्रालय स्तर पर होना चाहिए और मॉनिटरिंग के द्वारा जो राज्य सरकारें सरकारी खरीद की प्रक्रिया में आनाकानी करती हों या अनियमिततायें करती हों, ऐसी राज्य सरकारों को मंत्रालय के अन्य मदों से दी जाने वाली सहायता राशि रोकी जानी चाहिए ताकि किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों की खरीद समय पर हो सकें एवं किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।